विचार बिन्दु

आनंद वह ख़ुशी है जिसके भोगने पर पछताना नहीं पड़ता। –सुकरात

सरकार काम कर रही है यह बताने के लिये ग्राम रथ

सरकारें जब काम करती हैं तो उन्हें अपना काम आम जनता को दिखाना भी होता है ताकि सत्तारूढ दल के सदस्य जब फिर वोट मांगने अवाम के बीच जायें तो उन पर यह तोहमत न लगे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। लेकिन हमने यह भी देखा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार के कामों का भयंकर प्रचार भी चुनाव में किसी काम नहीं आया था। हमने राजस्थान में भी विधानसभा के पिछले चुनावों में धुआंधार प्रचार के बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सत्ता से बाहर होते देखा है। अब इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है। अब सरकार के पूरे कार्यकाल में प्रचार अभियान सतत चलाया जाने लगा है। एक के बाद एक सरकारी ईवेंट किये जाने लगे हैं, जिससे उसके वे काम जनता को दिखें जिसे वह बताना चाहती है। ऐसा ही एक ईवेंट 'ग्राम रथ' का राजस्थान में चल रहा है। सरकारें विकास कार्य करती हैं, योजनाएं बनाती हैं और उन्हें लागू करती हैं, परंतु यह सब तब तक राजनीतिक रूप से सार्थक नहीं होता जब तक वह आम जनता की चेतना में न दिखने लगे। इसके लिये पेशेवर प्रचार विशेषज्ञ नये-नये तरीके ईजाद करते रहते हैं। उनका नया आइडिया यह है कि प्रचार चुनाओं के समय ही नहीं सतत चलता रहना चाहिए ताकि संदेश मतदाताओं के मस्तिष्क में ठीक से बिठाया जा सके। इसके पीछे प्रचार उद्योग का अपना मुनाफा भी है। पहले प्रचार उद्योग मनोरंजन जगत तथा उपभोक्ता वस्तुओं निर्माताओं अथवा किसी संस्थान या ब्रांड की छवि चमकाने के लिये काम करता था। नई सदी में उनकी मांग राजनीतिक जगत में भी होने लगी है। सत्तारूढ राजनैतिक दलों को यह लाभ होता है कि उनका ज्यादातर प्रचार का खर्च सरकार के कामों के प्रचार के नाम पर राजकोष से हो जाता है। इसलिए आश्चर्य नहीं कि सरकारों का प्रचार पर खर्च साल-दर-साल बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। इसी परिपेक्ष्य में हम राजस्थान सरकार के वर्तमान में चल रहे 'प्रचार रथों' के अभियान को समझ सकते हैं। राजस्थान सरकार के प्रचार का यह केवल साधारण सूचना अभियान नहीं हैं, बल्कि ऐसे अभियान आधुनिक राजनीतिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण बनकर उभर रहे हैं। इन्हें केवल प्रचार का माध्यम मानना एक सीमित दृष्टिकोण होगा। इनके पीछे कई परतों वाली रणनीति कार्य करती है कि शासन लोगों को दिखे, जिसका लाभ निर्वाचित प्रतिनिधियों को मिले। इसलिए इस बात का कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि बीजेपी के पदाधिकारी इन रथों के सारथी बनाये गए हैं।

डिजिटल युग में भी भारत का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां प्रत्यक्ष संपर्क का महत्व बना हुआ है। प्रचार रथ इस प्रत्यक्ष संपर्क का माध्यम बनते हैं। इसीलिए राजस्थान की 200 में से 183 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे रथ चल रहे हैं। ये सभी क्षेत्र ग्रामीण हैं। शेष 17 विधानसभा क्षेत्र शहरी हैं जहां इनकी जरूरत नहीं समझी गई हैं। शायद ऐसा माना गया है कि वहां स्मार्टफोन पर सीधे या इन्फ़्लुएन्सरों के जरिए प्रचार को पहुंचा दिया जाएगा। सरकारी योजनाएं अक्सर जटिल होती हैं और उनकी जानकारी हर नागरिक तक स्वत: नहीं पहुंचती। कई बार लाभार्थी स्वयं यह नहीं जान पाते कि उन्हें जो सुविधा मिल रही है, वह किस योजना के अंतर्गत है। इसलिए कहा जा सकता है कि ग्राम रथ इस अंतर को पाटने का प्रयास कर रहे हैं। वे यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार सक्रिय और संवेदनशील है। यह दिखाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र में जो दिखता है, वही अक्सर सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। प्रत्येक ग्राम रथ एक छोटा वाहन है जिस पर कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन लगी है। इसमें ड्राइवर के साथ एक व्यक्ति है जिसका काम है कि कंप्यूटर में दी गई वीडिओ क्लिप जगह-जगह चला कर लोगों को दिखाना। करीब 15 क्लिप मिलाकर कुल लगभग एक घंटे की हैं। सभी में बताने का प्रयास किया गया है कि मौजूदा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में क्या काम किये हैं। इस अभियान की गंभीरता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि इस प्रचार पर मुख्यमंत्री कार्यालय तथा शासन तंत्र के प्रमुख मुख्य सचिव स्तर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

सूचना और जनसंपर्क विभाग इन रथों का संचालन जिला परिषदों के माध्यम से कर रहा है। रथ के ठहराव के स्थानों पर स्थानीय कलाकारों के प्रदर्शन भी शामिल किये गए हैं। ग्राम रथों से ग्रामीण आबादी कितनी प्रभावित हो रही है इसका पता तो जब चुनाव होंगे उनके परिणाम ही देंगे मगर अभी ऊपर से सारा जोर इस बात पर है कि रथ के कार्यक्रमों में जो लोग आ रहे हैं उनकी विडियो रिपोर्टें सोशल मीडिया पर निरंतर डाली जाए। सब जगहों से रथों के इवेन्टों के फ़ोटो और विडिओ डलवाने के लिये जयपुर में बैठे प्रशासन के आला अफसर दिन रात नीचे के लोगों को हैरान-परेशान किये हुए हैं। यहां हमें उस मूल द्वंद्व को समझना होगा जो आज की राजनीति में गहराई से मौजूद है-काम (सरकार का प्रदर्शन) बनाम धारणा (परसेप्शन)। यह नये जमाने में लोकतंत्र का बदलता समीकरण है। लोकतंत्र के आदर्श स्वरूप में यह माना जाता है कि मतदाता सरकार के कार्यों का मूल्यांकन कर वोट देता है। लेकिन व्यवहार में स्थिति ऐसी होती नहीं है। मतदाता का निर्णय केवल ठोस उपलब्धियों पर आधारित नहीं होता, बल्कि उसकी अपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक धारणाओं से भी उसका मन प्रभावित होता है जिसके आधार पर वह वोट देता है। आम आदमी का सरकारी तंत्र से पड़ने वाले रास्ते से भी उसकी सरकार के प्रति धारणा बनती है। लोग अक्सर अपनी धारणाओं के आधार पर वोट देते हैं। यह धारणा कई कारकों से बनती है जैसे मीडिया, सामाजिक संवाद, व्यक्तिगत अनुभव और राजनीतिक प्रचार। प्रचार रथ इस धारणा को नियंत्रित और दिशा देने का प्रयास करते हैं। वे एक कथा गढ़ते हैं कि सरकार विकासोन्मुख है, जनहितैषी है और लगातार काम कर रही है। यह कथा बार-बार दोहराई जाती है ताकि वह मतदाता के मन में स्थायी रूप से बैठ जाए। इसके साथ ही अब केंद्र तथा अधिकांश राज्यों में बीजेपी की सरकारें भावनाओं की अपनी राजनीतिक पूंजी में अपने काम को भी बड़े पैमाने पर शामिल कर रही है ताकि संवैधानिक व्यवस्थाओं से बंधे शासन में भी उसकी वह पैठ भी बने जो उसके भावनात्मक नेरटिव के हिसाब से हो तथा मतदाता का चुनावी व्यवहार उसके पक्ष में प्रभावित हो। सरकार के विकास के कामों के प्रचार से सरकार अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास तो करती ही है, साथ ही वह विपक्ष के नैरेटिव का प्रत्युत्तर भी परोक्ष रूप से देती है। लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार की आलोचना करना है। यदि विपक्ष यह धारणा बनाने में सफल हो जाता है कि सरकार निष्क्रिय है या विफल है, तो यह सत्तारूढ दल के लिए खतरा बन सकता है। प्रचार के ये रथ इस चुनौती का जवाब हैं। वे एक वैकल्पिक कथा प्रस्तुत करते हैं। मगर सरकारी कोष और मशीनरी के जरिए चलाए जा रहे रथ अभियान पर यह सवाल उठना स्वाभाविक ही है कि क्या यह लोकतांत्रिक आवश्यकता है या राजनीतिक प्रचार? यह प्रश्न इस पूरे विमर्श का सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद पहलू है। एक दृष्टिकोण से देखें तो जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलनी आवश्यक है। सरकार को अपने कार्यों का लेखा-जोखा देना चाहिए। संचार के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। इस दृष्टि से शासन में बैठे लोगों को प्रचार रथ एक लोकतांत्रिक आवश्यकता प्रतीत होते हैं। लेकिन दूसरी ओर जब सरकारी संसाधनों का उपयोग सत्तारूढ दल की छवि सुधारने के लिए होता है, तो यह राजनीतिक प्रचार बन जाता है। इसमें उपलब्धियों को अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है और कमियों को छिपाया जाता है।

लोकतंत्र के आदर्श स्वरूप में यह माना जाता है कि मतदाता सरकार के कार्यों का मूल्यांकन कर वोट देता है। लेकिन व्यवहार में स्थिति ऐसी होती नहीं है। मतदाता का निर्णय केवल ठोस उपलब्धियों पर आधारित नहीं होता, बल्कि उसकी अपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक धारणाओं से भी उसका मन प्रभावित होता है जिसके आधार पर वह वोट देता है।

ऐसे में निजी क्षेत्र में फल-फूल रहे प्रचार व्यवसाय को सरकार के इमेज मैनेजमेंट काम भरपूर मिल रहा है। प्रचार के रथ लोकतंत्र और राजनीति के बीच की उस धुंधली रेखा पर चलते हैं जहां जन-सूचना और राजनीतिक स्वार्थ एक-दूसरे में घुल-मिल जाते हैं। आज की राजनीति में सफलता का समीकरण बदल चुका है। अब केवल काम करना पर्याप्त नहीं है, और धारणा बनाना भी जरूरी है। इसके लिये प्रभावी संचार आवश्यक हो गया है। राजनीतिक दलों ने यह समझ लिया है कि काम आधार है, धारणा प्रभाव है और संचार पुल है जो दोनों को जोड़ता है। ग्राम रथ इसी पुल का निर्माण करने मे लगे हैं। वे उस जटिल वास्तविकता का हिस्सा हैं जहां सरकारें काम भी करती हैं और उसे दिखाने की आवश्यकता भी महसूस करती हैं। इसके लिये वे राजकोष का इस्तेमाल करने में परहेज नहीं करतीं। आज का मतदाता जागरूक भी है, लेकिन सोशल मीडिया के जाल में फंसा मतदाता धारणा से अधोक प्रभावित होता है। इन्हीं परिस्थितियों में राजनीति सेवा और रणनीति के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है और राजनेता अपने को जनता से सम्बद्ध रखने का प्रयास करते हैं। अंतत:, लोकतंत्र की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करेगी कि मतदाता कितनी सजगता से इन प्रचार माध्यमों को परखता है। यदि नागरिक केवल दिखावे से प्रभावित होंगे, तो राजनीति भी उसी दिशा में जाएगी। लेकिन यदि वे वास्तविक काम और ठोस परिणामों को प्राथमिकता देंगे, तो प्रचार की सीमाएं स्वत: तय हो जाएंगी। इसलिए, असली प्रश्न यह है कि हम, मतदाता, उस प्रचार को कितनी समझदारी से ग्रहण करते हैं।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं समीक्षक)

लोकतंत्र और पार्टी हाईकमान : निर्णय और निर्णायक

रामनिवास बैरवा

राजनीतिक पार्टियों के निर्णय लोकतान्त्रिक व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव डालते हैं। जब कोई राजनीतिक पार्टी ही अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया को लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के अनुसार नहीं ढाल सकती, तब देश का लोकतान्त्रिक आधार तो डांवाडोल होता ही है; उसकी भागीदार राजनीतिक पार्टियां भी, क्रमश: समाप्त होने को बाध्य होती हैं।

भारतीय जनता पार्टी का 'कांग्रेस मुक्त भारत' जैसा नारा या अभियान उसी ही बाध्यता का एक रूप है, जिसमें लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को तिलांजलि देकर 'हाई कमान' के चारों और अपने अनुयायियों को इकट्ठा करके राजनीति में सफल होने का खेल कर रहे होते हैं। यही 'हाई कमान' की निर्णायक भूमिका की परम्परा ही भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता से बाहर का रास्ता दिखायेगी।

जब ऐसी पार्टियों का आधार लोकतंत्र नहीं होकर 'पार्टी हाई कमान' ही निर्णायक बन जाते हैं तो सिद्धांतहीनता के अभाव में वे दूसरों पर लांछन लगाते हैं, आपस मे एक दूसरे का चरित्रहनन करते हैं। और फिर इस प्रकार से सभी पार्टियां गलीच बनकर रह जाती हैं और अपने प्रतिद्वंद्वी को भी उसी गलीच चरित्रहनन के स्तर पर ले आती हैं, तब सब एक जैसे हो जाते है।

लेकिन जनता उन पार्टियों के द्वारा आपसी चरित्रहनन के साथ-साथ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी आदि को भी समय-समय पर अपना नारा बनाये रखने को बाध्य करती हैं। चूंकि भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी पूंजीवादी लोकतन्त्र के ऐसे आवश्यक विषय हैं, जिनको बनाये रखना उनके लिए आवश्यक है। उनको खतम करना उन कथित राजनीतिक पार्टियों के लिए घातक होता है, अत: कुछ और नया जोड़ने की कोशिश की जाती रही है।

जहां कांग्रेस गांधीजी को और स्वतंत्रता प्राप्ति को अपनी परम उपलब्धी होने का बखान करती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी धार्मिक रूढ़ियों को सनातन सत्य बताकर अपनी राजनीतिक सत्ता को बनाये रखने का प्रयासरत रही है। लेकिन जिस संविधान आढ़ में राजनीतिक पार्टियां सत्ता प्राप्त करती हैं, उसी संविधान को अपनी-अपनी सत्ता के स्थायित्व में अवरोध भी मानती हैं। अत: वे संविधान की व्याख्या अपने-अपने स्वार्थों के अनुसार करती हैं और नौकरशाहों का उपयोग करती है, विचारधारा को छोड़ देती हैं। इस प्रकार से लोगों की विचार भिन्नता को दवाये रखने के लिए एक ही व्यक्ति के आदेशों के अनुसार चलने की परम्परा डाली जाती है। पार्टी हाई कमान बनने का सबसे पहला प्रयोग 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में किया गया था। उस समय, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद उसके अनुयायियों के द्वारा कांग्रेस के मंच पर मोहम्मद अली जिन्ना को बेइज्जत करके मंच से ही नहीं कांग्रेस से भी हट जाने को मजबूर किया था तथा 'महात्मा' बनने के चक्कर में गांधीजी ने वह सब बाखुशी देखा और मौन रहकर कांग्रेस पार्टी की अलोकतान्त्रिक कार्य प्रणाली के 'हाई कमान' बने।

उसके बाद, जब तक गांधीजी जिंदा रहे, कांग्रेस के हाई कमान बने रहे और मरने के बाद राष्ट्रपिता बना दिये गये। लेकिन, 1920 में चरित्रहनन करने वालों को आगे की सम्भावनाएं कम दिखी, इसीलिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नामक संस्था बनाकर आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से 'कांग्रेस विहीन भारत' का नारा देकर, उसी 'हाई कमान' वाली व्यक्ति केंद्रित राजनीतिक पार्टी के सहारे, बेशक सत्ता भोग कर रही हो, लेकिन 'हाई कमान' के निर्णय लोकतन्त्र को नुकसान ही पहुंचाने वाले हैं।

संविधान का आध्याय-चार, 'राज्यों की नीति के निदेशक सिद्धांत' संविधान की आत्मा हैं और उनके लिए काम करना सभी सरकारों, सभी राजनीति पार्टियों के लिए सबसे बड़ा सिद्धांत है। उनके लिए काम नहीं करना गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा को निरन्तर बनाये रखना है, जिसका विपरीत परिणाम भ्रष्टाचार को अनिवार्यत: फलने-फूलने की परिस्थितियां निरन्तर बनाये रखना है। इस प्रकार उनके लिए, संविधान का अध्याय-चार, उनकी अपनी 'हाई कमान' प्रणाली के लिए कैसे रूकावट बना हुआ है, इसका एक ही उदाहरण देना काफी है।

गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार को, जो कि उनका 'मूल-अधिकार' है, को आंशिक रूप से समाप्त करने के लिए, भारत की समाज व्यवस्था में अछूत-पिछड़ी जातियों को उक्त अध्याय में, संदर्भ देकर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह आरक्षण व्यवस्था लोगों के आर्थिक-सामाजिक और राजनीतिक विकास के साथ ही जाति व्यवस्था और आरक्षण व्यवस्था के अनावश्यक बन जाने की अपेक्षा की गई थी। परन्तु, वही आरक्षण अब चुनावी लोकतन्त्र की आवश्यकता के साथ-साथ 'हाई कमान' की प्रणाली के लिए भी अनिवार्य बन गया है। कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जातियों को आरक्षण देने के संविधान के प्रावधान को अपना 'ट्रेडमार्क' मानती है, वहीं दूसरी अन्य पार्टियां विभिन्न जातियों के लिए आरक्षण को अपनी "हाई कमानका मास्टर स्ट्रोक" बनाने की कोशिशों में लगी हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जो सनातन व्यवस्था बनाये रखने को अपना ब्रांड या ट्रेडमार्क बना चुकी है, उस पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) के लिए आरक्षण को सनातनी व्यवस्था यानि कि वर्ण-व्यवस्था या जाति-व्यवस्था को समाज व्यवस्था का आवश्यक अंग अनाये रखने की आड़ में आरक्षण को खतम करने का स्पष्ट आरोप लगाया जा रहा है, उसी भारतीय जनता पार्टी की हाई कमान महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का दाव खेल चुकी है। परंतु 2026 में अभी हुए 5 विधान सभाओं के आम चुनावों में किसी भी पार्टी ने, यहां तक कि स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने भी महिलाओं को उक्त 33 प्रतिशत की मात्रा में चुनावों में टिकिट नहीं दिए।

महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का विरोध किसी भी राजनीतिक पार्टी का हाई कमान करना चाहता है। क्योंकि कथित महिला आरक्षण पुरूष सत्ता को और मजबूती देने कि ही प्रचारित किया गया है। आंकड़ों को देखें तो-

अभी संसद में 80-85 महिला सांसद है, जो कि 543 सांसदों का 15.65 प्रतिशत है। जाहिर है कोई भी राजनीति पार्टी, महिला आरक्षण के द्वारा नारी मुक्ति को जोर-शोर से प्रचार करने वाली भारतीय जनता पार्टी भी, संसद में 15 प्रतिशत से अधिक महिलाओं को चुनावी मैदान में नहीं उतार रही हैं। लेकिन महिला आरक्षण के नाटक के पीछे इन 15.65 प्रतिशत महिलाओं की सीटें भी अपने पुरूष उम्मीदवारों को देने की कोशिश में संविधान को ही अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए ढ़ाल बना चुकी हैं। क्योंकि महिलाओं को नईबढ़ाई जाने वाली 33 प्रतिशत सीटों में समेटा जायेगा और वर्तमान 15.65 प्रतिशत सीटें अपने पुरूष उम्मीदवारों को दे देंगी।

इसके अलावा एक और षड्यंत्र है इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी राजनीतिक पार्टियों का। और वह यह है कि वर्तमान में महिलाओं को उम्मीदवार बनाने से उनकी नये-पुराने पुरूष उम्मीदवारों को अपनी दावेदारी से हाथ धोना पड़ रहा हैं जो कि अपनी-अपनी पार्टियों में विद्रोह, पार्टियों के टूटने के साथ ही नई बनाकर नया हाई कमान का उभारना है जिससे जातियों पर उनकी पकड़ में फूट पड़ती है। इसीलिए 33 प्रतिशत संसद में सीटें बढ़ाकर "महिलाओं को आरक्षण" और उन्हें उसी सीमा में बांधकर रखना होगा, ठीक वैसे ही जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को सिर्फ उन्हीं के लिए आरक्षित संख्या तक ही सीमित रखा जा रहा है।

फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ रूख किया जाये।

राजीव गांधी की मौत के बाद, 1991 से कांग्रेस में कोई हाई कमान नहीं रही थी। तब तब के चुनाव आयुक्त टी. एन. शेषन ने कांग्रेस की फूट के बीच गांधी परिवार को फिर से हाई कमान की भूमिका में लाने के प्रयास में कथित चुनाव सुधार लागू किये, जिससे, अंतत: सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का रास्ता साफ हुआ और वह आज भी कांग्रेस की हाई कमान बनी हुई है। बेशक, राहुल गांधी को दूसरा हाई कमान बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन वह गांधी के सामने का जवाहर लाल नहीं है जो गांधी जी के बाद नया हाई कमान खड़ा कर सके। और यह राहुल गांधी की मानसिक सोच में नहीं है कि वह हाई कमान जैसे सर्व-सुविधाओं से संपन्न हैसियत को छोड़ दे। नरेंद्र मोदी भी नहीं चाहते कि कांग्रेस में राहुल गांधी की राजनीतिक हैसियत कम हो। क्यों कि वह राहुल गांधी के बहाने भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक जुट रख पा रहे हैं, अन्यथा जब कोई प्रतिद्वंद्वी ही नहीं होगा तो किससे लड़ा जायेगा। इसलिए, एक हाई कमान दूसरी हाई कमान के खिलाफ, यहां तक कि चरित्रहनन तक का खेल खेल कर चुनावों की उठा-पटक कर जा रही है। इनको ना तो संविधान की चिंता है, ना ही किसी अनुसूचित जाति-अनुसूचित जन-जाति के आरक्षण से ाई लेना-देना है और ना ही किसी प्रकार के महिला आरक्षण से कोई लेना-देना है, बस उनकी हाई-कमान की हैसियत बनी रहे, यही उनके लिए लोकतंत्र है और यही उनका लिखा या बिना लिखा संविधान है।

-राम निवास बैरवा,
पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

पोखरण परमाणु परीक्षण : 51 वर्ष बाद भी शौर्य, समस्याएं और विकास की अधूरी कहानी बयां करता परीक्षण स्थल

51 वर्ष बीत जाने के बाद भी खेतोलाई और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत समस्याएं पूरी तरह दूर नहीं हो पाई हैं

जुगल किशोर बिस्सा

पोकरण भारत की सामरिक शक्ति, वैज्ञानिक क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा का गौरवशाली प्रतीक माना जाता है। राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित इस छोटे से कस्बे ने वर्ष 1974 और 1998 में हुए परमाणु परीक्षणों के कारण पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। लेकिन राष्ट्रीय गौरव के साथ-साथ इस क्षेत्र के लोगों को अनेक समस्याओं और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा।

18 मई 1974 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने स्माइलिंग बुद्धा नाम से पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसके बाद 11 और 13 मई 1998 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ऑपरेशन शक्ति के तहत पांच परमाणु परीक्षण कर भारत को विश्व की परमाणु शक्तियों में शामिल कर दिया।

इन परीक्षणों के बाद पोकरण का नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। देशभर में इसे राष्ट्रीय गौरव के रूप में देखा गया। वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सहित भारतीय वैज्ञानिकों की भूमिका को सराहा गया। वर्ष 1998 के परीक्षणों ने भारत की रक्षा क्षमता को मजबूती दी और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति मजबूत हुई।

ग्रामीणों की समस्याएं और प्रभाव : परमाणु परीक्षण स्थल के सबसे निकट बसे खेतोलाई गांव के लोगों का कहना है कि परीक्षणों के बाद क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ीं। ग्रामीणों ने कैंसर, त्वचा रोग, आंखों में जलन, पशुधन पर प्रभाव तथा जन्मजात बीमारियों जैसी शिकायतें उठाई हैं। हालांकि इन दावों पर सरकार की ओर से कोई व्यापक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

ग्रामीणों का कहना है कि परीक्षणों के समय धरती हिल गई थी और कई घरों में दरारें तक आ गई थीं। कई परिवारों का आरोप है कि वर्षों से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन कोई स्थायी मेडिकल रिसर्च या विशेष स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई।

मूलभूत सुविधाओं का अभाव : राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने के बावजूद आज भी पोकरण और आसपास के गांवों में कई मूलभूत समस्याएं बनी हुई हैं। खेतोलाई सहित आसपास के क्षेत्रों में पेयजल संकट, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार का अभाव और खराब आधारभूत ढांचे की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। कई रिपोर्टों में बताया गया है कि गांवों में पानी की सप्लाई कई-कई दिनों बाद होती है तथा ग्रामीणों को टैंकरों से पानी खरीदना पड़ता है।

ग्रामीणों का कहना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर्याप्त रूप से संचालित नहीं हो पाते तथा विशेषज्ञ डॉक्टरों और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। युवाओं को रोजगार के लिए बाहर पलायन करना पड़ता है।

केंद्र सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं :- परमाणु परीक्षणों के बाद केंद्र सरकार तथा रक्षा संस्थानों द्वारा कुछ विकास कार्य जरूर किए गए। क्षेत्र में सेना और रक्षा प्रतिष्ठानों की मौजूदगी से सड़क और संचार व्यवस्था में सुधार हुआ। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई तथा परीक्षण क्षेत्र को संरक्षित रखा गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर पोकरण को देश की वैज्ञानिक उपलब्धि के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

इसके अलावा रक्षा अनुसंधान एवं परमाणु कार्यक्रमों से जुड़े सीमित रोजगार अवसर भी क्षेत्र में बने। हालांकि स्थानीय लोग लंबे समय से विशेष पैकेज, कैंसर अस्पताल, बेहतर पेयजल योजना, पर्यटन विकास, शिक्षा संस्थान और युवाओं के लिए रोजगार की मांग कर रहे हैं।

मई महीने में ही परीक्षण क्यों किए गए? :- भारत सरकार द्वारा पोखरण में परमाणु परीक्षण मई महीने में अलग-अलग समय पर किए जाने के पीछे कई सामरिक, वैज्ञानिक और मौसम संबंधी कारण माने जाते हैं। विशेषज्ञों और रक्षा विश्लेषकों के अनुसार यह केवल संयोग नहीं था, बल्कि रणनीतिक योजना का हिस्सा था।

रेगिस्तानी मौसम और साफ वातावरण : -पोकरण थार मरुस्थल क्षेत्र में स्थित है। मई महीने में यहां अत्यधिक गर्मी रहती है और आसमान सामान्यत: साफ रहता है। वैज्ञानिकों के लिए भूमिगत परीक्षण, उपकरणों की निगरानी और सैन्य गतिविधियों को संचालित करना आसान माना गया। गर्म हवाओं और धूल भरे वातावरण के कारण विदेशी उपग्रहों की निगरानी से भी कुछ हद तक बचाव संभव माना जाता था।

विदेशी जासूसी उपग्रहों से बचाव : 1998 के परीक्षण अत्यंत गोपनीय तरीके से किए गए थे। उस समय अमेरिका सहित कई देशों के जासूसी उपग्रह भारत की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। वैज्ञानिकों और सेना ने रात के समय काम किया तथा गर्म मौसम और रेतीले इलाके का फायदा उठाकर तैयारियां छिपाई। माना जाता है कि मई की तेज गर्मी और धरती की ऊष्मा के कारण उपग्रहों को स्पष्ट गतिविधियां पकड़ने में कठिनाई हुई।

रणनीतिक और राजनीतिक समय : -1974 के परीक्षण के समय भारत वैश्विक दबाव के बावजूद अपनी परमाणु क्षमता दिखाना चाहता था। वहीं 1998 में भारत ने खुद को खुलकर परमाणु शक्ति घोषित करने का निर्णय लिया। उस समय क्षेत्रीय सुरक्षा, विशेषकर चीन और पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियां, एक बड़ा कारण थीं।

भूमिगत परीक्षण के लिए उपयुक्त स्थिति :- वैज्ञानिकों के अनुसार मई में जमीन की सूखी और कठोर स्थिति भूमिगत परीक्षणों के लिए उपयुक्त मानी गई। इससे विस्फोट को नियंत्रित रखने और रेडियोधर्मी प्रभाव को सीमित करने में मदद मिली।

11 मई का विशेष महत्व :- 11 मई 1998 को हुए पोखरण-परीक्षणों के बाद भारत ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित किया। इसी ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है।

क्या कोई धार्मिक या ज्योतिषीय कारण था? :- कुछ लोगों द्वारा समय-समय पर धार्मिक या ज्योतिषीय कारणों की चर्चा की जाती रही है, लेकिन सरकार या वैज्ञानिकों ने कभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की। उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार परीक्षणों का समय मुख्य रूप से सुरक्षा, गोपनीयता, मौसम और सामरिक रणनीति को ध्यान में रखकर तय किया गया था।

आज भी कायम है गौरव और उपेक्षा का द्वंद्व :- पोकरण आज भी भारत की सामरिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। यहां हुए परमाणु परीक्षणों ने भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस भूमि ने देश को परमाणु शक्ति बनाया, उसी क्षेत्र के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

51 वर्ष बीत जाने के बाद भी खेतोलाई और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत समस्याएं पूरी तरह दूर नहीं हो पाई हैं। ग्रामीणों की मांग है कि केंद्र और राज्य सरकारें पोकरण को परमाणु नगरी के रूप में विशेष दर्जा देकर यहां आधुनिक अस्पताल, कैंसर उपचार केंद्र, उच्च शिक्षा संस्थान, पर्यटन विकास, पेयजल परियोजनाएं और युवाओं के लिए रोजगार के स्थायी अवसर उपलब्ध करवाएं, ताकि राष्ट्रीय गौरव के साथ स्थानीय जनता का जीवन स्तर भी बेहतर हो सके।

–जुगल किशोर बिस्सा,
वरिष्ठ पत्रकार।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 13 मई, 2026

प्रथम ज्येष्ठ मास (शुद्ध), कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2083, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दिन 1:30 तक, विष्कुम्भ योग रात्रि 8:35 तक, बालव करण दिन 1:30 तक, चन्द्रमा आज मीन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मेष, चन्द्रमा-मीन, मंगल-मेष, बुध-मेष, गुरू-मिथुन, शुक्र-वृष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज राजयोग दिन 1:30 से रात्रि 12:18 तक है। आज अपरा एकादशी, भद्रकाली एकादशी, जलक्रीड़ा एकादशी (उड़ीसा), पंचक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:04 तक, शुभ 10:43 से 12:23 तक, चर 3:42 से 5:22 तक, लाभ 5:22 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 5:44, सूर्यास्त 7:02

मेष
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना पड़ सकता है। आज समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा।

वृष
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है।

कर्क
आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि का भय है। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आज अटके हुए कार्य